भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1931
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

महाराष्ट्र में भारतनेट परियोजना

1931. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः
श्री संजय उत्तमराव देशमुखः
श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के उन गांवों का ब्यौरा क्या है, जो अब तक 4जी और फाइबर कनेक्टिविटी से वंचित हैं, और इसके विलंब के कारण क्या हैं;
(ख) देश में पूर्ण ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;
(ग) महाराष्ट्र में, विशेषकर वाशिम-यवतमाल क्षेत्र में, भारत नेट चरण-III के अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है;
(घ) क्या इस परियोजना के अंतर्गत जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के वाशिम-यवतमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, भारत नेट परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;
(छ) परियोजना के 2011 में प्रारंभ होने के बाद से अब तक इसके धीमे कार्यान्वयन के कारण क्या हैं; और
(ज) परियोजना के कार्यान्वयन में बहुत पिछड़ गए जिलों के नाम क्या हैं और इसके कारण क्या हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ङ) महाराष्ट्र सहित देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी)/ गांवों को ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ने के लिए नेटवर्क का निर्माण करने हेतु भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में, भारतनेट के तहत दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार 27,689 ग्राम पंचायतों (जीपी) में से 24,575 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान कराने के लिए तैयार कर दिया गया है। दिसंबर 2025 तक महाराष्ट्र राज्य के 43,931 गांवों में से 42,716 गांवों को 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किया गया है। राज्य में भारतनेट के कार्यान्वयन के तहत मार्ग का अधिकार के मुद्दे, कई एजेंसियों की भागीदारी आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन सभी चुनौतियों का समाधान संबंधित एजेंसियों के साथ योजना बनाकर और समन्वय के साथ किया जा रहा है।

संशोधित भारत नेट कार्यक्रम (एबीपी) को महाराष्ट्र के वाशिम-यवतमाल क्षेत्र सहित देश में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। एबीपी के तहत निर्माण चरण के पूरा होने की समय-सीमा करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि से तीन वर्ष है। इसके अलावा, एबीपी महाराष्ट्र में जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों सहित अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए लगभग 28,237 ग्राम पंचायतों और 15,799 बिना ग्राम पंचायत (जीपी) वाले गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

(च) से (ज) दिनांक 31.12.2025 तक पूरे देश में भारतनेट कार्यक्रम के तहत कुल 2,14,904 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान कराने के लिए तैयार कर दिया गया है जिसमें महाराष्ट्र के वाशिम-यवतमाल क्षेत्र की 1,239 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

भारतनेट परियोजना देश के दूरदराज के कोनों में व्यापक रूप से फैली हुई है जो दुर्गम क्षेत्रों (पहाड़ी/ चट्टानी) और दुर्गम पहुंच वाले वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों को भी कवर करती है। भारतनेट का कार्यान्वयन कोल्हापुर, नासिक, पुणे, रत्नागिरी, सतारा और ठाणे जिलों में प्रभावित हुआ है जिसमें इस परियोजना का कार्यान्वयन मार्ग का अधिकार संबंधी मुद्दे, कई एजेंसियों से अपेक्षित अनुमति, विकास कार्यों के कारण बिछाई गई ओएफसी को बड़े पैमाने पर हुई क्षति आदि जैसी चुनौतियों के कारण प्रभावित हुआ है।

*****